शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक-25 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 13-20 जून 2022 मूल्य पांच रूपए

कैग रिपोर्ट ने किया केंद्रीय सहायता का सच बेनकाब

- तीन वर्षों में नहीं मिला एक भी पैसा
- तीन वर्षों में बजट अनुमानों के मुकाबले करीब 40 हजार करोड़ ज्यादा खर्च
- क्या यह खर्च पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज
- अकेले चुनावी वर्ष 2019-20 में है अनुमान और वास्तविक खर्च में 27000 करोड़ का अंतर

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पखवाड़े में दो बार हिमाचल आ गये हैं। पहले शिमला में 31 मई को मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर आये। जिस गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सरकारी योजना के लाभार्थियों को बुलाया गया था। सम्मेलन अच्छा हुआ। लेकिन कर्ज के चक्रव्यू में ही से प्रदेश को उबारने के लिये कोई आर्थिक सहायता नहीं दे गये। बल्कि जिस तरह से अपने सहयोगी मंत्री अनुराग ठाकुर का अपने संबोधन में नाम तक भी नहीं लिया वह खबर भी बना और राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना। शिमला के बाद 15 से 17 जून तक धर्मशाला में राज्यों के मुख्य सचिवों के पहले सम्मेलन को दो-दिन का समय दे दिया। इस सम्मेलन में भी अनुराग ठाकुर का शिमला ही की तरह नजरअंदाज होना फिर खबर बना। लेकिन इस सम्मेलन में शामिल होने के लिये आते समय हवाई अड्डे के बाहर अग्निपथ योजना से आक्रोशित युवाओं का आक्रोश भी झेलना पड़ा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिये सरकार और संगठन ने पन्द्रह हजार से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिये कांगड़ा चंबा के सारे विधायकों और दूसरे नेताओं को संगठन की ओर से लक्ष्य दिये गये थे। लेकिन सम्मेलन में पन्द्रह हजार की जगह पांच हजार ही जुट पाये। केवल देहरा के होशियार सिंह और नूरपुर के राकेश पठानिया ही अपना लक्ष्य पूरा कर पाये अन्य नेता नहीं। इस सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री प्रदेश को कुछ देकर नहीं गये। क्योंकि यह मुख्य सचिवों का सम्मेलन था। लेकिन यहां पर तय लक्ष्य पन्द्रह हजार की जगह पांच हजार की भीड़ का ही जुट पाना अपने में कई सवाल खड़े कर गया है। क्योंकि कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और सरकार बनाने का रास्ता यहीं से निकलता है। एक अरसे से कई कांग्रेस नेताओं के नाम उछलते रहे हैं कि वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब पलटकर यह चर्चा भाजपाईयों के ही गिर्द आती जा रही है। कांगड़ा में जब केजरीवाल आये थे तब उन्हें घेरने के लिये कोई भाजपाई सामने नहीं आ पाया और यह काम मेजर मनकोटिया से करवाना पड़ा। अब प्रधानमंत्री के आगमन पर माना जा रहा था कि मनकोटिया भाजपा में शामिल हो जायेंगे। मोदी के स्वागत में मनकोटिया द्वारा एक दैनिक में जारी किया गया विज्ञापन इसका संकेत माना जा रहा था। लेकिन मोदी के आगमन पर अग्निपथ से आक्रोशित युवाओं के आक्रोश ने मनकोटिया के पावं फिर जकड़ दिये। इसी के साथ इस सम्मेलन में भी अनुराग ठाकुर की अनदेखी को लेकर बनी खबरों ने प्रदेश की सियासत को फिर से हिला कर रख दिया है। यह चर्चा चल पड़ी है कि मोदी द्वारा पीठ थपथपाने से ही सत्ता की वापसी का रास्ता नहीं खुल जायेगा। यह वापसी जय राम के काम पर निर्भर करेगी। जयराम के काम पर अब तक आयी कैग रिपोर्ट जो स्वाल उठाये हैं उनका जवाब अभी तक नहीं आ पाया है। बल्कि केंद्रीय सहायता के दावों को लेकर तो स्थिति बहुत ही हास्यस्पद हो गयी है क्योंकि मोदी से लेकर नड्डा, जय राम तक सभी ने लाखों से हजारों करोड़ केंद्र द्वारा प्रदेश को दिये जाने के दावे किये हैं। लेकिन यह 31 मार्च 2020 तक की आयी कैग रिपोर्ट ने इन दावों के झूठ की पोल खोल कर रख दी है। कैग के मुताबिक 2015-16 से 2019-20 तक चार मदो गैर योजना गत अनुदान, राज्य की स्कीमों हेतु अनुदान, केंद्रीय स्कीमों हेतु अनुदान और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान में राज्यों को एक पैसा भी नहीं मिला है। जबकि 2015-16 और 2016-17 में मिला है। तब भी केंद्र में मोदी की ही सरकार थी। आज प्रदेश पर जो 70 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया है उसके लिये केंद्र कि इस बेरूखी को भी कारण माना जा रहा है। इन तीन वर्षो में सरकार के अनुमानित बजट और वास्तविक खर्च हुये बजट में करीब 40 हजार करोड़ का अंतर है। अकेले 2019-20 के खर्च में ही 27 हजार करोड़ का फर्क रहा है। क्योंकि इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव भी हुये हैं। ऐसे में स्वभाविक है कि अनुमानों से अधिक खर्च करना पड़ा है सरकार को। यह खर्च पूरा करने के लिये जब केंद्र ने कुछ नहीं दिया तो स्वाभाविक रूप से कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प सरकार के पास नहीं बचा था। शायद इसी कारण से 100 से अधिक स्कीमों पर सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर पायी है। कैग रिपोर्ट के इस खुलासे पर सरकार कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं कर पायी है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब 69 राष्ट्रीय राजमार्गो से लेकर लाखों हजारों करोड़ की केंद्र से सहायता मिलना जुमलो से अधिक कुछ नहीं रहा है तो फिर सत्ता में वापसी के दावे क्या ईवीएम के भरोसे किये जा रहे हैं।

तालिका-1.1: 2015-20 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	9,207	8,788	10,135	9,728	11,230	11,009	13,331	11,438	14,351	12,335
सामाजिक सेवाएं	9,676	7,980	11,388	9,610	11,884	10,337	13,488	11,482	13,895	12,047
आर्थिक सेवाएं	6,407	5,525	7,314	5,996	7,734	5,697	9,082	6,512	7,832	6,338
अन्य	5	10	5	10	9	10	11	10	11	10
योग (1)	25,295	22,303	28,842	25,344	30,857	27,053	35,912	29,442	36,089	30,730
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	2,991	2,864	3,241	3,499	3,531	3,756	4,298	4,583	4,580	5,174
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	397	463	428	3,290	448	503	448	468	457	458
लोक ऋण की अदायगी	1,503	3,948	2,229	3,943	3,105	3,500	3,184	4,673	3,262	6,701
लोक लेखा संवितरण	2,978	10,577	3,103	12,351	3,303	13,043	3,303	14,493	3,303	20,111
अंत रोकड़ शेष	--	216	--	316	--	183	--	53	--	1,060
योग (2)	7,869	18,068	9,001	23,399	10,387	20,985	11,233	24,270	11,602	33,504
सकल योग	33,164	40,371	37,843	48,743	41,244	48,038	47,145	53,712	47,691	64,234

स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्त लेखे।

तालिका-1.2: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजनागत अनुदान	8,524	8,877	--	--	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	756	1,188	--	--	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	38	44	--	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान	1,978	3,055	--	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	--	--	3,590	4,010	4,915
वित्त आयोग के अनुदान*	--	--	8,889	8,831	8,618
अन्य अंतरण/राज्य/विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान	--	--	615	2,276	2,406
योग	11,296	13,164	13,094	15,117	15,939
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	57.37	16.54	(-) 0.53	15.45	5.44

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

समाज का कद बढ़ता है, साहित्यकारों से:राज्यपाल

शिमला/शैल। तीन दिनों से हिमाचल की राजधानी शिमला में चल रहे देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव के समापन सत्र के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गेयटी थियेटर के मुख्य सभागार में उपस्थित साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा कि साहित्यकारों से किसी भी समाज का कद बढ़ता है, और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी को इस भव्य समारोह का मेजबान बनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि समाज को दिशा देने वाला साहित्य ही सच्चा साहित्य होता है। उन्होंने साहित्यकारों से अपील की कि वे उन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को भी लेखन का आधार बनायें जिन्हें समाज ने विस्मृत कर दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए गुलज़ार के उस कथन का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पटकथा को साहित्य माना जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों में पुस्तक पढ़ने की रुचि विकसित करने के लिए माता-पिता और साहित्यकारों से आगे आने का आह्वान किया।

समारोह के प्रारंभ में साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि इतना बड़ा सफल आयोजन बिना हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए उन्होंने सभी स्थानीय सहयोगी संस्थाओं को विशेष धन्यवाद देते हुये कहा कि इस सहयोग से प्रोत्साहित होकर हम आगे भी इस तरह के बड़े आयोजन कर पाने में समर्थ होंगे। समापन समारोह में साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार, हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक राकेश कंवर भी उपस्थित थे। अंत में साहित्य अकादेमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने सभी

प्रतिभागियों एवं श्रोताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस समारोह के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में मैं क्यों लिखता/लिखती हूँ विषयक परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुये प्रख्यात गुजराती साहित्यकार एवं साहित्य अकादेमी के महत्तर सदस्य रघुवीर चौधरी ने कहा कि मेरा प्रथम प्रेम कविता ही है। मेरे लिये लिखना ही जीवन है और मैं जीने के लिये ही लिखता हूँ। उन्होंने पत्रकारिता द्वारा भी अपने सृजन अनुभव के समृद्ध होने की बात कही। एक अन्य बहुभाषी रचना-पाठ और मेरे लिये कविता के मायने? विषयक सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रख्यात हिंदी कवि अरुण कमल ने कहा कि ''पत्थर के भीतर से पानी की आवाज को भी पकड़ लेना कविता है''। कविता मृत्यु से जीवन की तरफ लाती है और हमारी भाषाओं का सुंदर संगीत खोजती है। आगे उन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी प्राथमिक कविताएँ हैं और उनमें हमारे समय की गति को समझा जा सकता है।

समापन सत्र पर आयोजित 23 विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुये कुछ प्रमुख साहित्यकार और विद्वान थे- केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान, मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, जेरी पिंटो, विश्वास पाटिल, चिन्मय गुहा, रीता कोठारी, चमन लाल गुप्त, रमेश आर्य, अभिराज राजेंद्र मिश्रा, संजुक्ता दास गुप्ता, वाई.डी. थोंगछी, अष्टभुजा शुक्ल, सुदर्शन वशिष्ठ, एस.आर.हरनोट आदि। समारोह के अंतिम दिन एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिचर्चा-विदेशी भाषाओं में भारतीय साहित्य की अध्यक्षता अमेरिका से पधारी साहित्यकार लिंडा हेस ने की और इसमें फ्रांस, डोमिनिकल रिपब्लिक, उज़्बेकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बंगलादेश, थाइलैंड, नेपाल एवं भारत के साहित्यकारों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

समापन सत्र पर अंतिम सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत प्रख्यात दास्तानगो महमूद फ़ारूक़ी ने दास्तान-ए-कर्ण अज़ महाभारत की यादगार प्रस्तुति दी।

प्रेरणा के स्रोत हैं श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश: राज्यपाल

शिमला/शैल। गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा शिमला और प्रदेश सरकार के सहयोग से शिमला के

ऐतिहासिक रिज मैदान में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित हुए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को नमन करते हुए राज्य के लोगों की सुख-समृ) की कामना की। उन्होंने सिख समुदाय को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि श्री तेग बहादुर जी ने विश्व शांति और मानव सुख के लिए प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उन्होंने समाज को विभिन्न बुराइयों से मुक्त करने का प्रयास करते हुए अच्छाई और मूल्यों की शिक्षा प्रदान की। राज्यपाल ने सिख समुदाय द्वारा की जा रही सेवा की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं, संदेश और उनके द्वारा दिए गए सबक आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने धर्म और आस्था के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सामाजिक समरसता के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं।

इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, जत्थेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह और बड़ी संख्या में सिख संगत भी उपस्थित थी।

सोशल ऑडिट के माध्यम से कामगार कल्याण बोर्ड देगा योजनाओं की जानकारी

शिमला/शैल। प्रदेश की कुल 3615 ग्राम पंचायतों में से 863 पंचायतों में सोशल ऑडिट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक किया जायेगा। इसके साथ-साथ लोगों के बीच जाकर इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में लोगों से जानकारी भी प्राप्त की जाएगी।

इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश सोशल ऑडिट के निदेशक के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने विवेकानंद केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में कांगड़ा जिले के केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

राज्यपाल ने इस महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और विचारों को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे।

इस अवसर पर विवेकानंद शिला

स्मारक और विवेकानंद केन्द्र के उपाध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि हनुमंत राव और केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के कुलपति एस.पी. बंसल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

राज्यपाल ने धर्मशाला में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरोह का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के अपने दो दिवसीय दौरे के

दौरान धर्मशाला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरोह का दौरा किया। उन्होंने नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों से संवाद किया।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को पुस्तकें भेंट कीं और जीवन में पढ़ने की आदत अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ने से सकारात्मक सोच विकसित होती है। हमें किताबों से दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि उनसे हमें ज्ञान मिलता है। उन्होंने छात्रों से उनके द्वारा दी गई पुस्तकों को पढ़ने और पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा।

अग्निपथ योजना से युवाओं का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होगा:वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशु पालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने सेना भर्ती के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लॉच की गई अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस निर्णय पर देश के युवाओं को भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हैं।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुये और सेना में सेवा के उनके उत्साह को देखते हुए इस योजना को पुरानी व्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपनों को पूरा करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। इससे युवा सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात कर सक्षम बन सकेंगे। इस योजना से बेहतरीन कौशल, प्रमाणन और डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा, क्रैडिट के माध्यम से वे आसानी से समाज से जुड़ने में सक्षम होंगे।

उन्होंने कहा कि इस योजना से वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण, टीम निर्माण क्षमता, लोकाचार और भाई-चारे की भावना वाले आत्मविश्वास से भरे बेहतर नागरिकों का निर्माण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सेवा के चार वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त अच्छा वित्तीय पैकेज युवाओं को अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं जिम्मेवार बनायेगा और उन्हें उच्च शिक्षा के लिये कौशल संबंधी सर्टिफिकेट एवं क्रेडिट प्रदान किये जायेंगे।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त विपक्षी दल उन पर हो रही जांच से लोगों का ध्यान भटकाने के लिये इस योजना के बारे में दुष्प्रचार कर अपने लाभ के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है।

उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि अग्निपथ योजना के बारे में सटीक एवं तथ्यपरक जानकारी के लिए वे सरकार एवं सेना की ओर से जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के बेहतर भविष्य और भारतीय सेना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त पद भरने के लिए कदम उठाए जायेंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला मंडी में नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के आइरिस-2022 के समापन समारोह के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मंडी का मेकशिफ्ट अस्पताल कोरोना महामारी के पूर्ण रूप से समाप्त होने के उपरान्त सुपर स्पैशियलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा तथा चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस चिकित्सा महाविद्यालय की प्रगति को स्वयं देखा है। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्देश्य उच्च क्षमता, समर्पित तथा संवेदनशील चिकित्सकों के माध्यम से उच्च गुणात्मक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह महाविद्यालय मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति तथा बिलासपुर जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महाविद्यालय में 23 विभाग कार्यशील है तथा अन्य विभागों की स्थापना के लिए प्रक्रिया जारी है। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 120 सीटों की क्षमता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए चिकित्सा विद्यार्थियों को जीवन की एकरूपता को बदलने के लिए अपना मनोबल बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में समाज की पीड़ा को दूर किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि चिकित्सकों को भी मनोरंजन के कुछ पल मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा प्रदेश होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में आज केवल सरकारी क्षेत्र में ही छः चिकित्सा महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों के 500 पद भरने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशिक्षु चिकित्सकों के स्टाईपंड को बढ़ाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदान के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महाविद्यालय की पत्रिका एसक्लेपियस का विमोचन किया। उन्होंने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शपथ भी दिलवाई। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न आयोजनों के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए।

महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल वर्ष 2018 में 250 बिस्तर क्षमता के साथ आरम्भ किया गया था लेकिन आज अस्पताल की बिस्तर क्षमता 500 है। उन्होंने अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लगभग 20 पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जिससे अब अस्पताल में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है।

महाविद्यालय के एससीए के अध्यक्ष सचिन ग्रेवाल ने कहा कि आइरिस फेस्ट 2022 में लगभग 1150 एमबीबीएस विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें से 450 विद्यार्थी राज्य के पांच अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों से भाग ले रहे हैं।

सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल, नाचन के विधायक विनोद कुमार, बल्ह के विधायक इंदर सिंह गांधी, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, जिला परिषद मंडी के अध्यक्ष पाल वर्मा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा रजनीश पठानिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिये अग्निपथ योजना को स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ एक दूरदर्शी योजना है जो देश की सेवा तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरभूमि के नाम से जाना जाता है तथा प्रदेश के सपूत सैन्य बलों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह योजना देश तथा प्रदेश के युवाओं को सैन्य बलों में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत इस वर्ष 46000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, जिससे रोज़गार अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत देश में बाहरी व आंतरिक खतरों तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे सैन्य बलों में नई युवा ऊर्जा समाहित होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत अग्निवीरों को पहले वर्ष 30000 रुपये, दूसरे वर्ष 33000 रुपये, तीसरे वर्ष 36500 तथा चौथे वर्ष 40000 रुपये का आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज प्रदान किया जाएगा। चार वर्ष की कार्य अवधि के पूर्ण होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपये की एकमुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जायेगा जिससे उन्हें बिना किसी आर्थिक दबाव के अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। योजना के तहत अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कौशल व योग्यता बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए सेवाएं प्रदान करने के उपरांत अग्निवीरों को पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा वे युवाओं के लिए रोल मॉडल बनकर उभरेंगे।

जन भागीदारी से सुशासन–हिमाचल का महाक्विज़ एक अनूठी पहल:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने यह बात सोलन जिला के बद्दी में

आयोजित जन भागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महाक्विज के उद्योग और निवेश विषय पर आधारित दूसरे राउंड के समापन समारोह को शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए तकनीक का उपयोग करके जन भागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महाक्विज़ के आयोजन की अनूठी पहल की है। इसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में पहली बार केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि महाक्विज़ में प्रतिभागी भारी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी तक इसमें लगभग 40 हजार प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। पहले राउंड में 23467 दूसरे राउंड में 14407 और तीसरे राउंड में 14000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस महाक्विज में हिस्सा लिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस महाक्विज़ के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं को जानने और समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से लोग और जागरूक होंगे तथा सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। हिमाचल पावर सरप्लस राज्य है, यहां कानून व्यवस्था बेहतरीन है और राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। प्रदेश की इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग 16वें स्थान से सातवें स्थान पर पहुंची है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई, जिसमें 96 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये और बहुत ही कम समय में हजारों करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने फार्मा हब के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बनायी है। एशिया की 45 प्रतिशत दवाइयां हिमाचल के उद्योगों से निर्यात हो रही हैं। कम संसाधन वाले इस छोटे राज्य में प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। योजना में महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दी गई है। इस योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इसके माध्यम से 11000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रदेश के तीव्र एवं संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रदेश सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

बद्दी में आयोजित समारोह में विधायक परमजीत सिंह पम्मी व लखविंदर राणा, पूर्व विधायक के. एल. ठाकुर, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, महाक्विज़ के प्रतिभागियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति के विषय में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की स्थिति की समीक्षा के लिए निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के.सी. चमन ने सरकारी तेल विपणन कम्पनियों और डीलरों तथा सभी हितधारकों के साथ बैठक की।

बैठक में तेल कम्पनियों के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के भारी संख्या में आगमन और पड़ोसी राज्य से हिमाचल प्रदेश में वैट कम होने के कारण सीमावर्ती जिलों में जून माह में पेट्रोल और डीजल की खपत में भारी वृद्धि हुई है। सभी तेल विपणन कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है और शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

इंडियन ऑयल ने पुष्टि की कि उनकी ओर से पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की राशनिंग नहीं की जा रही है।

बैठक में सभी तेल कम्पनियों को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन स्टॉक की समीक्षा करें तथा ऐसे स्थानों पर जहां एक ही पेट्रोल पम्प है, को प्राथमिकता पर तेल उपलब्ध करवायें। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये गये कि वे प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति की रिपोर्ट निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के साथ साझा करें। तेल कम्पनी के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने ग्राहकों से पेट्रोल और डीजल की अनावश्यक खरीद व भण्डारण न करने का आग्रह किया।

डीपीआईआईटी के सचिव ने हिमाचल के स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्ज से संवाद किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग ने धर्मशाला में सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) भारत सरकार अनुराग जैन के साथ राज्य के स्टार्टअप इन्क्यूबेटरों के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। अनुराग जैन ने राज्य में स्टार्टअप्स की एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें 24 स्टार्टअप्स ने आईटी, स्वास्थ्य, खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आदि क्षेत्रों से संबंधित अपने नये विचारों/उत्पादों/सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। सचिव, डीपीआईआईटी ने राज्य सरकार के निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति के साथ राज्य इनक्यूबेशन केंद्रों के आठ नोडल अधिकारियों के एक समूह के साथ बातचीत की, जिसमें निफ्ट के निदेशक आकाश देवांगन ने भी हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में निदेशक उद्योग ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप, नवाचार परियोजनाओं, नई उद्योग योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति और चुनौतियों के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए उठाये गये कदमों, स्टार्टअप नीति पर हुई प्रगति, और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाये गये रोड मैप को साझा किया। उन्होंने भारत सरकार से राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, जिस पर सचिव, डीपीआईआईटी ने आश्वासन दिया कि राज्य को स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुराग जैन ने स्टार्टअप्स के प्रेरकों के साथ बातचीत की। उन्होंने उनकी स्टार्टअप यात्रा पर उनके विचारों जाना तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में उद्योग विभाग द्वारा किये गये प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने स्टार्टअप्स को अपने स्टार्टअप विचारों के व्यावसायीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

यह विरोध कहीं विद्रोह न बन जाये

सेना में पिछले दो वर्षों से कोई भर्ती नहीं हो पायी है यह इसलिये नहीं हो पाया है क्योंकि वर्ष 2020 को 2021 में देश कोरोना के कारण लॉकडाउन में था। लेकिन इसी दौरान कुछ राज्यों में विधानसभा के लिये चुनाव हुये हैं। लोकसभा के लिये उपचुनाव भी हुये। सरकार चुनावों का प्रबंध तो कर पायी लेकिन सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 62 लाख पदों को भरने का उपक्रम नहीं कर पायी। अकेले सेना में ही दो लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। जबकि 2014 और 2019 के चुनाव के दौरान यह वादा किया गया था कि 2 करोड पद सृजीत करके भरे जायेंगे। लेकिन यह वादा केवल जुमला होकर ही रह गया। सेना में भर्तियां न हो पाने के कारण लाखों युवा इसके लिये ओवरेज भी हो गये हैं। सेना में प्रतिवर्ष 50,000 से ज्यादा सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेना की व्यवहारिक स्थिति क्या होगी। कई युवा तो ग्राउंड और लिखित टेस्ट क्लियर करने के बाद मेडिकल के लिये काल आने की प्रतीक्षा में थे। लेकिन जब 14 जून को अग्निपथ योजना अधिसूचित हुई और यह कहा गया कि अब इस योजना के तहत छयालीस हजार अग्निवीर भर्ती होंगे और उनका कार्यकाल केवल चार वर्ष का होगा तथा उनमें से 75% को सेवानिवृत्ति करके घर भेज दिया जायेगा। इसका असर उन युवाओं पर क्या हुआ होगा जो सेना में अपना भविष्य देख रहे थे। यह योजना आते ही उनके आगे अंधेरा छा जाना स्वभाविक था। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि आज सरकार सेना में भी स्थायी रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं रह गई है। हिमाचल में ही सेना नौकरी का कितना बड़ा साधन है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि सेना भर्ती तुरंत चालू की जाये।

जो सरकार सेना में भी नियमित नौकरी देने की स्थिति में न हो क्या उसकी नीयत और नीति दोनों पर ही प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहिये? आज सेना में स्थायी रोजगार पाने की उम्मीद में बैठे लोगों को अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिये किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी नेतृत्व के तहत संगठित नहीं होना पड़ा है। 14 तारीख को योजना अधिसूचित होती है और 15 को प्रधानमंत्री के धर्मशाला आने पर उनके स्वागत में लगाये गये बैनर,पोस्टर, होल्डिंग विरोध से फाड़ दिये जाते हैं। पुलिस को आक्रोशित युवाओं को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। यह गुस्सा स्वभाविक और घोर निराशा का स्वत: प्रमाण था। इस आक्रोश के समझने की यह किसी राजनीतिक दल के नाम लगाने से हल होने या रुकने वाला मामला है। यह सवाल आज हर जुबान पर हैं कि आखिर रोजगार खत्म कैसे हो गया? इसका जवाब प्रधानमंत्री से लेकर बूथ पालक तक को देना होगा की रोजगार पैदा करने वाले हर अदारे को प्राइवेट सैक्टर के हवाले क्यों कर दिया गया? यह भी जवाब देना पड़ेगा कि लॉकडाउन में पहला फैसला मजदूर का हड़ताल का अधिकार छीनने का क्यों लिया गया? यह भी बताना होगा कि लॉकडाउन और हड़ताल का अधिकार समाप्त करके उद्योगों में रोबोट संस्कृति लाकर हाथों को बेकार क्यों किया गया? किसान को कमजोर करने के फैसले के बाद जवान को कमजोर करने का यह फैसला क्यों लिया गया?

अग्निपथ योजना की जिस तरह और तर्क से एक वर्ग वकालत करने पर उतर आया है उससे 2019 में सैनिक स्कूलों को प्राइवेट सैक्टर को देने के फैसले पर ध्यान जाना स्वभाविक है। क्योंकि आज सैनिक स्कूलों के संचालन में आरएसएस का नाम सबसे प्रमुख है। विद्या भारती के माध्यम से इनका संचालन किया जा रहा है। इससे यह सवाल उठने लग पड़ा है कि क्या देश की सेना भी संघ की विचारधारा के अनुरूप बनाने की योजना का यह अग्निपथ पहला चरण तो नहीं है। अग्निपथ के साथ ही देश में पेट्रोल-डीजल का संकट खड़ा होने लग गया है। इसी संकट के साथ खाद्यानों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री इस सब पर खामोश हैं। वह 2047 तक की योजनायें देश के मुख्य सचिवों के साथ बनाने में व्यस्त हैं। ऐसे में क्या देश दूसरे जे.पी.आंदोलन की ओर बढ़ रहा है जिसका नेतृत्व यह आक्रोशित युवा करेगा। क्योंकि दूसरे नेतृत्व के लिये आयकर, ईडी, सीबीआई और एन आई ए जैसी कई एजेंसियां खड़ी है। लेकिन नौकरी की उम्मीद में बेरोजगार बैठे इस आक्रोशित युवा को यह एजेंसीयां नहीं रोक पायेंगी।

मुश्किल समय में केरल और झारखंड से आये हैं सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश

गौतम चौधरी

आज के भारत में जैसे-जैसे भेदभाव, हिंसा बढ़ी हैं, वैसे-वैसे सांप्रदायिक सौहार्द के उदाहरण भी राहत के तौर पर सामने आये हैं। जब सांप्रदायिक सद्भाव के संकेत सुर्खियों में आते हैं, तो सद्भाव और सह-अस्तित्व की पिछली स्मृति को फिर से जीवित करने की आशा को बल मिलता है। इस्लामोफोबिया और नफरत को कायम रखने के गढ़े गये आख्यान ने हमारे सामाजिक जीवन को जटिल बना दिया है, और मुसलमानों और हिंदुओं के पड़ोसियों के रूप में रहने की कल्पना करना भी कठिन बना रहा है। हालांकि, भारत की विविधता का जश्न मनाते हुये शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से जुड़ी यादें, आशायें और आशावाद हमेशा हमारे साथ हैं।

अभी हाल ही में विगत 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद रांची के मेन रोड में हिंसा भड़क गयी। हिंसक भीड़ पत्थरबाजी पर उतारू थे। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गये लेकिन जब अल्वर्ट एक्का चौक पर उसी हिंसक भीड़ में एक पुलिसकर्मी फंस गया तो दो मुस्लिम नौजवानों ने यह कहते हुए उक्त पुलिस की सहायता की हमें अपने धर्म में यह नहीं सिखाया गया है कि निर्दोश को हानि पहुंचायें। हालांकि पूरी हिंसक भीड़ पुलिस को पूरी तरह हानि पहुंचाने के फिराक में थे लेकिन उस नौजवान ने उक्त पुलिस की जान बचाई। इस हिसा के बीच रांची से निकलने वाली एक प्रतिनिधि उर्दू अखबार, ''दैनिक फारूखी तंजीम'' ने हिंसा के खिलाफ अपील का विज्ञापन छाप कर संवेदनशील मीडिया होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। फारूखी तंजीम के स्थानीय संपादक गुलाम शाहिद ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया खाते भी शांति की अपील के अपील वाले संदेश पोस्ट किये।

तमाम उथल-पुथल के बीच, इसी प्रकार के सांप्रदायिक सदभाव के उदाहरण केरल से भी आये हैं। केरल के एक मंदिर ने स्थानीय मुसलमानों के लिये इफ्तार समारोह आयोजित करके सांप्रदायिक सद्भाव और सहिष्णुता की आशा को फिर से जगा दिया है। केरल के मलप्पुरम जिले के थिरुर में विष्णु महादेव मंदिर के मैदान में 7 अप्रैल को मंदिर के प्रबंधन निकाय द्वारा आयोजित सामूहिक इफ्तार के लिए लगभग 300 मुस्लिम एकत्र हुये। यह आयोजन सामाजिक संबंध और सामुदायिक जीवन की भावना को ध्यान में रख कर किया गया था। दोनों समुदायों ने एक-दूसरे के अस्तित्व को अपनी सामाजिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया है और एक-दूसरे पर परस्पर निर्भरता का कोण भी है, इसलिए वे इस विशिष्टता का जश्न मनाते हैं।

वे एक-दूसरे के दैनिक जीवन में भाग लेते हैं क्योंकि वे दैनिक कार्यों पर अपनी निर्भरता को पहचानते हैं, और त्यौहार केवल उस बंधन को मनाने के अवसर हैं। मंदिर समिति के सचिव सुकुमारन वी. ने बताया कि इफ्तार के बारे में जो बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, वह यह है कि हमारे कई मुस्लिम मित्र रमजान के कारण मंदिर उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित वार्षिक सामूहिक भोज में शामिल नहीं हो सके। हमारे लिए, यह एक बड़ी कमी होगी क्योंकि हम अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों की मदद और समर्थन से त्योहार का आयोजन करते थे। उन्होंने आगे कहा कि 'विचार-विमर्श करने के बाद, मंदिर समिति ने समुदाय के मुस्लिम सदस्यों के लिए इफ्तार आयोजित करने का फैसला किया। पंचायत के एक सदस्य और मुस्लिम लीग के एक स्थानीय नेता अब्दुल समद ने कहा कि हम सभी मंदिर द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल होने के लिए बहुत खुश और सम्मानित महसूस करते हैं, मैंने गैर-मुसलमानों द्वारा आयोजित कई इफ्तार पार्टियों में भाग लिया है। मंदिर द्वारा आयोजित इफ्तार मेरे लिए एक नया अनुभव था, उन्होंने कहा, यह हमें एकजुटता और सुरक्षा की भावना देता है। हमें ऐसा लगता है कि इस अंधेरे समय में हमारे हिंदू भाइयों द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य पूर्ण संदेश विविध संस्कृतियों और सभी धर्मो के आवास का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जबकि देश के कई हिस्से सांप्रदायिक हिंसा का दंश झेल रहे हैं, केरल के थिरुर का विष्णु महादेव मंदिर सभी समान विचारधारा वाले भारतीयों के अनुसरण के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। इस प्रकार के हजारों उदाहरण हमारे देश में हैं लेकिन हमारी मीडिया उतना परिपक्व नहीं हो पायी है कि रचनात्मकता को उभारे। हमारे समाचार माध्यमों के लिये आज भी हिंसा, काम-वासना, राजनीतिक कहानियां और अपराध महत्वपूर्ण बने हुये हैं। इस चित्र को बदलना होगा अन्यथा, भविष्य के भारत में आम नागरिकों का जीना बेहद कठिन होगा।

मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना से स्वस्थ होगा बचपन, प्रदेश बनेगा कुपोषण मुक्त

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश ने चहुंमुखी विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाये है। राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनायें आरम्भ कर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गो के प्रति सेवाभाव रखते हुये राज्य सरकार ने उनके हितार्थ में विशेष योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। इनमें मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना (एमएमबीएसवाई) एक है, जो बच्चों को गुणवत्तायुक्त पोषण उपलब्ध करवा कर प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एमएमबीएसवाई योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं में कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चे के जन्म, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद लगभग तीन वर्ष तक बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिक आहार प्रदान करने में सहायता उपलब्ध करवाना है। इससे बच्चों की उचित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित होगी और कुपोषण की समस्या से बचा जा सकेगा।

इस योजना को वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में बच्चे और मां के पोषण स्तर के दृष्टिगत कार्य योजना तैयार करने की घोषणा की थी जिसे नीति आयोग के सहयोग से राज्य सरकार ने तैयार किया है।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 65 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के चार लाख से अधिक बच्चों, 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के पांच लाख से अधिक बच्चों, तीन लाख से अधिक किशोरियों और 94000 धात्री माताओं को लाभान्वित करेगी। योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त कुपोषित बच्चों, धात्री माताओं और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की खरीद के विकल्प प्रदान किये गये हैं। बच्चों को बाल्यकाल में होने वाली बीमारियों और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिये प्रदेश में डायरिया नियंत्रण, निमोनिया नियंत्रण, एनीमिया मुक्त हिमाचल जैसे विशेष अभियान चलाये जायेगें।

इस योजना से जन्म के समय कम वजन वाले 14 हजार नवजात शिशुओं, 13335 उच्च जोखिम वाले गर्भधारण, 912 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और 5169 मध्यम कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवायें ली जायेंगी। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के लिए प्रतिमाह अन्तिम शनिवार को बाल स्वास्थ्य क्लीनिक का आयोजन किया जायेगा। ऐसे नवजात शिशुओं को विटामिन-डी और आयरन ड्रॉप्स उपलब्ध करवाकर, इसकी कमी को पूरा किया जाएगा।

एमएमबीएसवाई में धात्री माताओं को स्तनपान करवाने और पूरक आहार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जायेगी। जन्म के समय कम वजन वाले कुपोषित शिशुओं के मामले में प्रत्येक किलो ग्राम वजन बढ़ने पर अभिभावक को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली धात्री माताओं को स्तनपान और पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करने का भी उचित प्रावधान किया गया है। इसके लिए ईसीडी 104 कॉल सेंटर को और अधिक प्रभावी बनाने, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली धात्री माताओं को उचित जानकारी प्रदान करने के लिए इस कॉल सेंटर में पोषाहार परामर्शदाताओं की संख्या बढ़ायी गयी है ताकि समय-समय पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं को स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया जा सके।

एमएमबीएसवाई योजना का लक्ष्य न केवल बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को ही इसमें शामिल करना है, बल्कि गर्भवती महिला के पति और परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जायेगा। योजना के सफल क्रियान्यवन के लिए चार स्तरीय निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणाली भी स्थापित की जायेगी, जिसमें विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ सरकारी स्तर पर समीक्षा भी की जायेगी। योजना में डेटा पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी के साथ लाभार्थियों का रिकॉर्ड रखने और उनकी ट्रैकिंग के लिए एक एप्लिकेशन को भी विकसित किया जायेगा।

यह योजना प्रदेश में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण के मानकों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी और इससे एनएफएचएस-5 के आंकड़ों में सुधार होगा।

1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबन्ध

व्यापक कार्य योजना के हिस्से के रूप में एसयूपी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रधानमंत्री की स्पष्ट अपील को पूरा करने के लिए सीपीसीबी ने 30 जून, 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक उपाय किये हैं। सीपीसीबी की बहु-आयामी दृष्टिकोण में जो उपाय शामिल हैं उनमें कच्चे माल की आपूर्ति को कम करना, प्लास्टिक की मांग को कम करने के लिए मांग पक्ष के उपाय, एसयूपी के विकल्पों को बढ़ावा देने के उपायों को सक्षम करना, प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल युक्तियां और जागरूकता पैदा करना तथा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य बोर्डों को दिशा निर्देशित करना है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियमावली, 2016 के अनुसार, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है। पीडब्ल्यूएम (संशोधित) नियम, 2021 के अनुसार, पचहत्तर माइक्रोन से कम के वर्जिन या रीसाइकिल्ड प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि पीडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के तहत पहले पचास माइक्रोन की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिद्र, 12 अगस्त 2021 की अधिसूचना, 1 जुलाई, 2022 से निम्नलिखित चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करती है, जिनकी उपयोगिता कम और गंदगी फैलाने की क्षमता अधिक है।

प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर- बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन स्थर्मोकोल,।

प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर रैपिंग या पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन, स्टिर से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर।

चिन्हित वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योगों को प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसपीसीबी/पीसीसी को प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को वायु/जल अधिनियम के तहत प्रचालन करने के लिए सहमति को संशोधित/निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीमा शुल्क प्राधिकरण को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है। लूप को पूरा करने के लिए, स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया जा रहा है कि एसयूपी मद उनके परिसर में नहीं बेचे जाएंगे और मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, यदि ये निकाय प्रतिबंधित एसयूपी मद बेचते पाए जाते हैं।

मौजूदा आपूर्ति के विकल्प के रूप में, एसयूपी के विकल्प को बढ़ावा देने के उपायों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। सीपीसीबी पहले ही कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के लगभग 200 निर्माताओं को एकमुश्त प्रमाण-पत्र जारी कर चुका है। इन प्रमाणपत्रों को नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है जो सरकार की व्यापार करने में सुगमता की नीति के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, इन विनिर्माताओं के प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। एमएसएमई की सहायता करने के लिए, सीपीसीबी, सीआईपीईटी के सहयोग से, एसयूपी के विकल्प हेतु रूपांतरण के लिए देश भर में एमएसएमई के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। रांची, गुवाहाटी और मदुरै में ऐसी तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। आईआईएससी और सिपेट जैसे अग्रणी तकनीकी संस्थानों के सहयोग से पेट्रो आधारित प्लास्टिक के विकल्पों का विकास भी किया जा रहा है।

मांग पक्ष पर, ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग वाले प्लास्टिक विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक कच्चे माल के विनिर्माताओं को चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक मदों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इन प्रयासों में नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, एसपीसीबी और स्थानीय निकाय सभी नागरिकों-छात्रों, स्वैच्छिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ, आरडब्ल्यूए, बाजार संघों, क रपोरेट संस्थाओं आदि की भागीदारी के साथ व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इससे पहले, सीपीसीबी ने अपने उत्पाद की पैकेजिंग में प्लास्टिक के उपयोग की जांच के लिए देश भर में गुटखा/पान मसाला निर्माण उद्योगों का औचक निरीक्षण किया था।

एक सक्षमकारी सहायता प्रणाली का निर्माण करने के लिए, सीपीसीबी आयोजित बैठकों द्वारा जारी परामर्शियों को प्रचालनगत करने के लिए राज्य बोर्डों की प्राथमिक सहायता कर रहा है ताकि संबंधित राज्यों में सभी शहरी स्थानीय निकाय उनकी मदद से दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। जून 2022 में सभी एसपीसीबी/ पीसीसी के अध्यक्षों के साथ एक केंद्रीय कार्यशाला के अतिरिक्त एसपीसीबी/ पीसीसी के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

अंत में, व्यापक स्तर पर दक्षता बढ़ाने के लिए कई डिजिटल युक्तियां की गई हैं। नागरिक भागीदारी को सक्षम करने के लिए, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा एक एसयूपी लोक शिकायत ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप में शिकायतों को ट्रैक करने की सुविधा के साथ जियोटैगिंग सुविधाएं हैं। प्रगति और दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए सीपीसीबी द्वारा जारी व्यापक निर्देशों के अनुपालन में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल बनाया गया।

सीपीसीबी भारत के हरित भविष्य के लिए एसयूपी प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख हितधारकों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से अधिसूचित वस्तुओं के एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक आइटम की सूची

1. प्लास्टिक स्टिक

ईयरबड,बैलून,कैंडी,आइस-क्रीम

2. कटलेरी मद

प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे

3. पैकेजिंग/रैपिंग फिल्म

मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट

4 अन्य मदें

पीवीसी बैनर $< 100\mu m$, डैकोरेशन के लिए पोली स्टाइरिन, डैकोरेशन के लिए पोली स्टाइरिन

भारत में स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को यूनेस्को की मान्यता मिली

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत, एनसीईआरटी के सीआईईटी ने वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार जीता

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत आईसीटी का उपयोग करने के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है। 17 मई, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या की शुरुआत की गई थी, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है ताकि बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सके। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद(एनसीईआरटी) की एक घटक इकाई को यूनेस्को के वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार 'सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 के अनुरूप, सभी के लिए शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने के लिए नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान करता है। बहरीन साम्राज्य के समर्थन से वर्ष 2005 में स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण और समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय निर्णायक मॉडल प्रति वर्ष दो सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में एक समारोह के दौरान 25,000 अमेरिकी डॉलर, एक पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है, जो इस वर्ष 24 जून, 2022 को आयोजित किया जाएगा।

सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और देश में शैक्षिक प्रणाली में समानता लाने के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सीआईईटी, एनसीईआरटी के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय बड़ी संख्या में ई-बुक्स, ई-कंटेंट-ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव, ऑगमेंटेड रियलिटी कटेंट, इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) वीडियो, ऑडियोबुक, टॉकिंग बुक्स आदि के डिजाइन, विकास और प्रसार में अथक और सावधानी से काम कर रहा है(स्कूल और शिक्षक शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ई-पाठ्यक्रम(ऑनलाइन/ऑफलाइन, ऑन-एयर टेक्नोलॉजी वन क्लास-वन चैनल, दीक्षा, ईपाठशाला, निष्ठा, स्वयं प्लेटफॉर्म पर स्कूल एमओओसी आदि का लाभ उठाकर मुख्य रूप से छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्विज़ जैसे डिजिटल कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उपरोक्त स्तंभों को संबोधित करने के लिए, पीएम ईविद्या-एक व्यापक पहल जो सभी प्रयासों को एकीकृत करती है और डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस प्रदान करती है, मई 2020 में शुरू की गई थी।

सीआईईटी, पीएम ईविद्या कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों सहित 12 पीएम ईविद्या डीटीएच टेलीविज़न चैनलों और लगभग 397 रेडियो स्टेशनों के व्यापक, लचीला, नैतिक और सुसंगत उपयोग के माध्यम से बच्चों को घरों तक सीखने में सक्रिय सहयोग शामिल था। ये प्रयास विशेष रूप से महामारी की स्थितियों में, जब स्कूल बंद थे, छात्रों तक पहुँच बनाने में मददगार थे। इन प्रयासों ने सीखने के अंतराल को रोकने में काफी हद तक मदद की।

ओल्ड पेंशन स्कीम को घोषणा पत्र में शामिल करेगी कांग्रेस

शिमला/शैल। विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री व घोषणा पत्र समीति के अध्यक्ष धनी राम शांडिल, विधायक रोहित ठाकुर, भवानी सिंह पठानिया इत्यादि ने बैठक में भाग लिया।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, सरकारी विवविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए कांग्रेस सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन बहाल करेगी। छत्तीसगढ़ व राजस्थान की कांग्रेस सरकारें इसे पहले ही बहाल कर चुकी हैं।

बैठक में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। 12 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं के लिए नई रोजगार नीति लाने का निर्णय लिया गया। इसे भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने, महिला सुरक्षा व बागवानी के लिए नई योजनाएं बनाने सहित नशा और खनन माफिया पर शिकंजा कसने को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया।

इन सब क्षेत्रों में व्यापक सुधार करने के लिए नई नीतियों का स्वरूप कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पेश करेगी। ग्रामीण लोगों की आय के साधन बढ़ाने की योजनाओं को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जायेगा। प्रदेश सचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता कानून भी लायेगी, जिससे लोगों को जनप्रतिनिधियों की आय के स्रोतों व वृद्धि का हर साल पता चल सकेगा।

अवशेषों के स्तर को कम करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाए

शिमला/शैल। कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना (ए.आई.एन.पी.ऑन पीआर) की 30वीं वार्षिक समीक्षा बैठक डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में हुई। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से संचालित एआईएनपी के 18 केंद्रों के सदस्य दो दिवसीय बैठक में भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल मुख्य अतिथि रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीडीजी क्रॉप साइंस डॉ.टी.आर.शर्मा और एडीजी प्लांट प्रोटेक्शन और बायोसेफ्टी डॉ. एससी दुबे ने बैठक में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

परियोजना का उद्देश्य बहु-स्थानीय पर्यवेक्षित क्षेत्र परीक्षण के आधार पर अच्छी कृषि पद्धतियों की सिफारिश करके कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना है। डेटा का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) के निर्धारण के लिये भी किया जाता है। यह उचित सुरक्षित प्रतीक्षा अवधि और फसल पूर्व अंतराल पर सलाह देता है ताकि खाद्य वस्तुओं में अवशेष निर्धारित सुरक्षित सीमा के भीतर अच्छी तरह से रहें।

डॉ. रविंदर शर्मा, निदेशक अनुसंधान ने इस मौके पर सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का महत्व बताया। सभा को संबोधित करते हुये प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि भले ही देश कीटनाशकों के औसत उपयोग में विषय में वैश्विक स्तर की तुलना में नीचे हो परंतु समय है की हमें इस औसत पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा की देश के प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर रासायनिक आधारित खेती के वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि मौजूदा तकनीक ने मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को कम कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता डेटा तैयार करने में पूरे भारत में 18 केंद्रों द्वारा किए गए कार्यो की सराहना करते हुए प्रोफेसर चंदेल ने छात्रों के माध्यम से विश्लेषण के लिए हिमाचल से दूध के नमूने बढ़ाने का सुझाव दिया क्योंकि फ़ीड बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से ही आती है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि एआईएनपी ऑन पीआर केंद्रों को आईसीएआर और परियोजना के तहत अनुसंधान के अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिए और अवशेषों के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने वाले किसानों के खेतों से नमूने एकत्र करने चाहिए।

प्रो. चंदेल ने कहा कि अनधिकृत कीटनाशकों और मिश्रित कमपाउंड ने एक बड़ी चुनौती पेश की क्योंकि किसान कम समय में विभिन्न रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से भविष्य की चुनौतियों के साथ अपने काम को सरेखित करने और अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करने का आहवान किया।

कार्यशाला के दौरान एआईएनपी ऑन पीआर की नेटवर्क समन्वयक डॉ. वंदना त्रिपाठी ने योजना की समग्र उपलब्धि और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने देश में खाद्य सुरक्षा और व्यापार पर कीटनाशक अवशेष परियोजना के महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में परियोजना के तहत उत्पन्न डेटा का उपयोग देश में किसानों द्वारा उनके उपयोग के लिए सीआई.बी.आर.सी. द्वारा नए कीटनाशकों के पंजीकरण की मंजूरी के लिए किया जा रहा है।

अपने संबोधन में डॉ.टी.आर.शर्मा और डॉ.एस.सी. दुबे ने इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यापार बढ़ाने के लिए कम एमआरएल सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों का पालन करने की आवश्यकता की वकालत की। डॉ. शर्मा का विचार था कि भले ही कीटनाशकों का उपयोग दुनिया की तुलना में कम हो लेकिन गैर-विवेकपूर्ण और गैर-अनुशंसित रसायनों का उपयोग एक बड़ी चुनौती है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सहयोगी अध्ययनों के माध्यम से राजस्व सृजन के लिए एआईएनपी ऑन पीआर और इसके तहत 13 एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर सराहना की।

इस अवसर पर चार प्रकाशन भी जारी किये गये। डा. जेके दुबे, डा. सपना कटना और डा. अजय शर्मा द्वारा लिखित कीटनाशक अवशेषों पर एआईएनपी सोलन केंद्र-एक नज़र और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग और डा.के.के. शर्मा और डा. वंदना त्रिपाठी द्वारा लिखित भिंडी और टमाटर पर कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग। डा. जे के दुबे, प्रधान अन्वेषक एआईएनपी पीआर, यूएचएफ नौणी ने इस मौके पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एआईएनपी ऑन पीआर के प्रधान अन्वेषक डा. बलविंदर सिंह, जिनका पिछले महीने निधन हो गया, के लिए एक शोक संदेश भी पढ़ा गया।

इस मौके पर डा. पीके चक्रवर्ती, पूर्व एडीजी और सदस्य एएसआरबी, डा. केके शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक एआईएनपी ऑन पीआर, डा. रविंदर शर्मा, निदेशक अनुसंधान, डा. दिवेंद्र गुप्ता, निदेशक विस्तार शिक्षा और सभी वैधानिक अधिकारी और विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे।

अग्निपथ भर्ती योजना देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने सेना में अग्निपथ भर्ती योजना को देश के युवाओं के भविष्य से एक बड़ा खिलवाड़ बताते हुए कहा है कि यह सेना में युवाओं के देश भक्ति के जज्बे को कम करेगा। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम के बाद केवल चार साल के लिये सेना में उनकी सेवा उनके साथ एक बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने देश व युवाओं के हित मे सेना की प्रस्तावित अग्निपथ योजना पर तुरंत रोक लगाने की मांग केंद्र सरकार से की है।

प्रतिभा सिंह ने एक ब्यान में देश प्रदेश में इस भर्ती के खिलाफ युवाओं में बढ़ते आक्रोश पर चिंता प्रकट करते हुये कहा कि देश के सेनाबलो में किसी भी भर्ती में कोई भी खिलवाड़ नही होना चाहिये।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि देश की रक्षा के लिये मर मिटने का जज्बा रखने वाले युवा ही सेना में भर्ती के लिये कड़ा परिश्रम करते है। उन्होंने कहा कि सेना में अंशकालिक भर्ती का कोई भी प्रयोग सही साबित नही होगा। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिये सैन्य बलों में किसी भी प्रकार की कमी देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा साबित हो सकती है, इसलिए सेना में भर्ती पूर्व निर्धारित नियमों व पूरे समय अवधि के लिये ही होनी चाहिए।

'आप' ने अग्निपथ योजना वापस लेने के लिये राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने अग्नीपथ योजना के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किये। आप के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा की यह अग्निवीर योजना देश और प्रदेश के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक ही नहीं बल्कि उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। साथ ही देश की सुरक्षा को हाशिये पर धकेलने वाली बात है। आप अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और युवाओं के साथ खड़ी है। इस योजना को वापस लेने के लिये आप ने हिमाचल के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों से आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके इस योजना का कड़ा विरोध किया और जल्द से जल्द अग्नीपथ योजना को वापस लेने का सरकार से आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से यह आंदोलन हिंसक रूप ले रहा है उसके लिये सरकार जिम्मेवार है। उन्होने कहा कि इस आंदोलन में आगजनी और पत्थरबाजी करे रहे शरारती तत्वो का हम विरोध करते हैं और उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।

मेरा बूथ, सबसे मजबूत के नारे के साथ हर घर जायेगी कांग्रेस

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी की प्रदेश कांग्रेस कार्यलय में कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई।

बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये रामलाल ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार व भाजपा की जनविरोधी नीतियों व निर्णयों के मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश चुनाव प्रबंधन कमेटी की यह दूसरी बैठक थी, जबकि पहली बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई थी।

रामलाल ठाकुर ने कहा कि बैठक में 25 जून को सोलन में जिला स्तरीय चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी, जिला के सभी वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक की कार्यकारणी, अग्रणी संगठनो के प्रमुख हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा व दिशा निर्देश जारी किए जायेंगे।

इसी तरह 26 जून को सिरमौर जिला की बैठक होगी। इनमें भी सभी जिला के पदाधिकारियों, पार्टी के वरिष्ठ नेता, ब्लॉकों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी अग्रणी संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे।

रामलाल ठाकुर ने बताया कि इसी तरह क्रमश: मंडी,कुल्लू, लाहुल स्पीति, किन्नौर और उसके बाद जिला शिमला की बैठक शिमला में होगी।

इस दौरान उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विधायक अनिरुद सिंह, पूर्व विधायक आदर्श सूद, कांग्रेस महासचिव यशवंत छजटा कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र बुशेहरी मौजूद थे।

अनुराग ठाकुर सुजानपुर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व करेंगे

शिमला/शैल। केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 21 जून मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के कटोच पैलेस सुजानपुर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व करेंगे।

जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में घोषित किया था कि दुनिया भर में इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय'मानवता के लिए योग' है।

प्रधानमंत्री 21 जून को मैसूर पैलेस ग्राउंड से IDY 2022 समारोह का नेतृत्व करेंगे जहां लगभग पंद्रह हजार योग उत्साही योग करेंगे। यह कार्यक्रम संसद सदस्यों, विभागों, मंत्रियों, गणमान्य व्यक्तियों, पूज्य योग गुरुओं और संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश में, प्रधान मंत्री के संदेश को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एलईडी स्क्रीन स्थापित की जायेगी। यह योग दिवस कार्यक्रम कांगड़ा किले, कुल्लू में पाराशर झील और अटल सुरंग में भी मनाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कांगड़ा जिले के कांगड़ा किले में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मंडी जिले के पाराशर झील में आईडीवाई समारोह का नेतृत्व करेंगे।

केंद्रीय खेल और गृह मंत्री निसिथ प्रमाणिक मुख्य अतिथि होंगे और हिमाचल प्रदेश में लेह-मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग में आईडीवाई समारोह का नेतृत्व करेंगे। सभी चार स्थान देश के 75 प्रतिष्ठित और विरासत स्थलों में से हैं।

इस वर्ष 21 जून 2022 को आईडीवाई 2022 को दुनिया भर में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है क्योंकि सरकार इसे पूरी तरह से चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के साथ जोड़ रही है।

समाज के सभी वर्गों के हजारों युवा और अन्य, पंचायती राज संस्थानों, युवा मंडलों, समुदाय आधारित नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स और रोवर्स और आम लोग हिमाचल प्रदेश के चार स्थलों आयोजित होने वाले आईडीवाई समारोह में भाग लेंगे।

नामित एजेंसी 'आर्ट ऑफ लिविंग' और आयुष विभाग के योग विशेषज्ञ, प्रतिभागियों को हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों पर सुबह-सुबह योग करने के लिए प्रेरित करेंगे।

संबंधित जिला प्रशासन ने प्रतिभागियों की बसों और परिवहन के अन्य साधनों की सुविधा और समय पर आगमन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था की है।

सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को जलपान और टी-शर्ट प्रदान किये जा रहे हैं, साथ ही सुरक्षित पेयजल और कार्यक्रम आयोजित करने के लिये बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी की गयी है।

सभी स्थानों पर यातायात और कानून व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, अग्निशमन सेवा का भी प्रबंध किया जा रहा है।

प्रासंगिक रूप से, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कैलेंडर में न केवल इस दिन को चिह्नित करेगा, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और देखने के तरीके में एक क्रांति का प्रतीक होगा।

नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुये मंत्री ने बताया कि आईडीवाई मनाने की तैयारी जोरों पर है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिन के माध्यम से, हमारा उद्देश्य पारंपरिक प्रथा को अपनाने में तेजी लाना और दुनिया को मन, शरीर और आत्मा के लिए इसके लाभों की याद दिलाना है।

आयुष मंत्री ने बताया कि इस वर्ष की थीम दुनिया के सामने आने वाली भू-राजनीतिक दुविधाओं पर विचार करती है और हर किसी को अपने परोपकारी और खुद को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से संभालने में मदद करने का प्रयास करती है।

आयुष मंत्री ने आगे बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में, देश में लगभग 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन अभिनव 'गार्जियन रिंग' कार्यक्रम का भी गवाह बनेगा, जिसमें विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित किये जा रहे सभी कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग देखी जायेगी, जो दुनिया के पूर्वी हिस्से से शुरू होकर सूर्य के साथ पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि अद्वितीय 'रिले' कार्यक्रम में लगभग 80 देश भाग लेंगे।

टिंबर ट्रेल घटना की जांच के आदेश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि बहुमूल्य मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार सदैव कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री सोलन के परवाणू स्थित टिंबर ट्रेल में केबल कार में फसे सभी 11 यात्रियों को सुरक्षित बचाये जाने के उपरांत उपस्थित पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश जारी कर दिये हैं।

इससे पूर्व, टिंबर ट्रेल में पर्यटकों के केबल कार में फंसने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री जोकि हमीरपुर में एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दूरभाष पर इस घटना की जानकारी दी और पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ की टीम भेजने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री दुर्घटना की जानकारी मिलने पर हमीरपुर से स्वयं परवाणू पहुंचे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं टिंबर ट्रेल होटल के संचालक से इस घटना की जानकारी प्राप्त की।

जय राम ठाकुर ने इस घटना में सुरक्षित बचाये गये सभी 11 व्यक्तियों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना।

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये समुचित पग उठाये जायेंगे।

उन्होंने इस अवसर पर बचाव कार्य में योगदान देने वाली टिंबर ट्रेल होटल की टीम और एनडीआरएफ कर्मियों की टीम से भी बातचीत की और समय पर बहुमूल्य मानवीय जीवन बचाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन, शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, अन्य भाजपा पदाधिकारी, उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी, पुलिस अधीक्षक सोलन वीरेन्द्र शर्मा, एनडीआरएफ के अधिकारी एवं कर्मचारी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अग्निपथ को लेकर देश के युवाओ में भारी आक्रोश:शुक्ला

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अग्निपथ के जन विरोध को दबाने के लिये सेना को अपनी ढाल बनाकर सेना की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निपथ योजना देश व युवा हित मे नही है।

शुक्ला ने कहा कि भाजपा की हट से देश आज बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कृषि कानून को लेकर किसानों को आंदोलन करना पड़ा अब अग्निपथ को लेकर देश के युवाओ में भारी आक्रोश है।

शुक्ला ने कहा है कि भाजपा ने आज देश की सेना की साख को भी दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार सेना में चार सालों के लिये भर्ती करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जिसे कभी सहन नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि युवाओं का इस योजना का विरोध वाजिब है और सेना में अल्पावधि नही निर्धारित पूरे समय के लिये की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की आवाज को नही दवा सकती। उन्होंने कहा कि देशहित में इस योजना पर तत्काल रोक लगाते हुये सेना में खाली पड़े पदों को तुरंत भरना चाहिये। उन्होंने कहा कि भाजपा को इसे प्रतिष्ठा का सवाल न बनाते हुये युवा हित में स्थाई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर वित्त और राजस्व श्रेणी में प्रदेश को मिला स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड

शिमला/शैल। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2021 में राष्ट्रीय स्तर पर वित्त और राजस्व श्रेणियों में प्रदेश को प्राप्त प्रथम पुरस्कार को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को भेंट किया। यह पुरस्कार इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की, कि विभाग भविष्य में भी इस तरह का श्रेष्ठ प्रदर्शन निरंतर जारी रखेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एचपी-वैट-आईटी परियोजना को लागू करने और लगभग 31 ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करने, करदाताओं और अन्य हितधारकों पर व्यापार से संबंधित अनुपालन भार को कम करने और युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों के बावजूद, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने लगभग वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 8500 करोड़ रुपये का संग्रह किया, जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 7000 करोड़ रुपये के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। राजस्व में यह वृद्धि विभाग द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों, फील्ड अधिकारियों को आईसीटी आधारित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान करने, फील्ड अधिकारियों और हितधारकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से बेहतर अनुपालना के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के कारण संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आबकारी ई-गवर्नेंस परियोजना के क्रियान्वयन करने के लिए भी स्कॉच पुरस्कार जीता है।

पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पर्यावरण डोगरा द्वारा योग शिविर आयोजित

शिमला/शैल। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 133 पैदल

वाहिनी (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण डोगरा ने बटालियन हेडक्वार्टर कुफरी और तत्तापानी व जलोगी कैंप स्थित कंपनियों में योग अभ्यास शिविर का आयोजन किया, जिसमें बटालियन के सभी जवानों ने सामूहिक रूप से हिस्सा लिया। इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि योग से शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता लाना था, ताकि लोग अपने जीवन में नियमित रूप से योग को शामिल करें। योग शिविर के दौरान जवानों ने सामूहिक रूप से अनेक योगासन किए।

इस अवसर पर कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, कमान अधिकारी 133 पैदल वाहिनी (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण डोगरा ने सभी से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया।

योगाभ्यास कार्यक्रम में योगा प्रशिक्षक ने कपालभाती, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, वज्रासन, योग ध्यान सहित अन्य योग क्रियाओं के अभ्यास के दौरान उनके लाभ के बारे में भी अवगत करवाया।

योग को दिनचर्या में शामिल करें युवा:उपायुक्त शिमला

शिमला/शैल। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय योग जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हो गया। ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के अंतिम दिन उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

दो दिवसीय इस योग जागरूकता कार्यक्रम के पहले दिन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने योग विषय पर चित्रकला वह नारा लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। दूसरे और अंतिम दिन विश्वविद्यालय प्रांगढ़ में क़रीबन सौ छात्र छात्राओं ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय सूचना ब्यूरो शिमला द्वारा योग अभ्यास करने वाले छात्र छात्राओं को टी-शर्ट वितरित की गयी।

कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपायुक्त ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चित्रकला में पहला दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः कंचन बाला , शिवानी व सावी प्राप्त किया।नारा लेखन में पहला दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः श्वेता, निकेतन व रुचेंद्र ने प्राप्त किया।

इस मौक़े पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त शिमला ने कहा कि योग को हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग से शरीर स्वस्थ रहता है पर जब शरीर स्वस्थ रहता है तो देश स्वस्थ रहता है। इस मौक़े पर केंद्रीय सूचना ब्यूरो के प्रमुख अनिल शर्मा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अर्पिता नेगी वे डॉक्टर सत्यप्रकाश पाठक मौजूद रहे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन से आप की गंभीरता आयी सवालों में

शिक्षा और सैनिक स्कूलों में प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी पर पार्टी खामोश क्यों

शिमला/शैल। हिमाचल की आम आदमी पार्टी इकाई की ओर से प्रदेश के स्कूलों की खस्ता हालत को आने वाले चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये प्रदेश इकाई ने अपने कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों से अपने आसपास के स्कूलों के साथ सेल्फी लेकर भेजने का आग्रह किया है। अभी जब अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने जारी की और इसको लेकर पूरे देश का युवा आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आया। यह आक्रोश हिंसक विरोध की शक्ल तक ले गया। देश के विपक्षी दलों ने इस योजना के खिलाफ अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएं जारी की है। इसी कड़ी में प्रदेश की आम आदमी इकाई ने भी राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है और इसे वापस लेने का आग्रह किया है। जबकि अब सेना की ओर से भी अधिकारिक रूप से यह ऐलान कर दिया गया है कि योजना वापस नहीं होगी। बल्कि भर्ती का शेडयूल जारी करने की बात की गयी है। स्वभाविक है कि इस ऐलान के बाद या तो यह विरोध गंभीर टकराव की शक्ल लेगा या स्वत: ही शांत हो जायेगा। क्या होता है यह आने वाला समय बतायेगा। लेकिन इस स्थिति में राजनीतिक दलों के लिये कुछ गंभीर सवाल अवश्य उछाल दिये हैं। इसमें भी हिमाचल के संदर्भ में आम आदमी पार्टी के लिये स्थिति और भी गंभीर होगी क्योंकि वह प्रदेश में एक तरह से राजनीतिक शुरुआत कर रही है। उसका कोई भी कमजोर प्रयास केवल सत्तारूढ़ भाजपा के लिये ही लाभकारी होगा और प्रदेश की आम जनता के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी इकाई ने प्रदेश के स्कूलों की दशा दिशा को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो-दो बार हिमाचल आकर शिक्षा पर संवाद आयोजित करके यह मंत्र प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे गये हैं। कितने स्कूलों का परिणाम क्या रहा है? कितनों के अपने भवन नहीं है? कितनों में कितने अध्यापकों की कमी है? कितने एक ही टीचर के सहारे चल रहे हैं? यह सारे आंकड़े रखते हुये राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह दावा किया है कि वह प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को सुधार देंगे। इसके लिए धन कहां से आयेगा? इसके जवाब में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने की बात कहकर एक मंत्री का नाम लिये बगैर यह उछाल दिया कि जो मंत्री पहले दो कमरों के मकान में रहता था अब उसकी हैसियत बेटे की शादी की दस-दस रिसैप्शन देने की कैसे हो गयी? इस कथन से थोड़ी देर तालियां तो मिल सकती है लेकिन यह प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। हिमाचल की आर्थिक और भूगौलिक स्थिति दिल्ली से अलग है। हिमाचल में शिक्षा की यह स्थिति क्यों है इस पर प्रदेश के नेताओं से विस्तार में बात आनी चाहिये थी। क्योंकि हर चीज के लिये संसाधन आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं और प्रदेश पहले ही 70 हजार करोड़ के कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का क्या रास्ता होगा? जब तक इस पर संतोषजनक प्रारूप सामने नहीं आयेगा पार्टी को लेकर गंभीरता नहीं आ पायेगी। आज केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ चुकी है इस नीति से आम आदमी पार्टी कितनी सहमत है इस पर अभी तक कोई शब्द नहीं कहा गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा संस्थानों के लिये वित्तीय स्वायतता की बात की गयी है। इस पर पार्टी का स्टैंड क्या है? इसी के साथ शिक्षा में प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी वित्तीय स्वायत्तता के संदर्भ में आने वाले समय का एक बड़ा मुद्दा होगा। जिस पर हर पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। लेकिन आप शिक्षा के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूरी तरह खामोश है। ऐसा लगता है कि उसके प्रदेश नेतृत्व ने शिक्षा नीति को पढ़ा ही नहीं है। केवल शिक्षा के नाम पर एक लोक लुभावन स्थिति खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अंत में राजनीतिक लाभ भी मिल पायेगा इसकी संभावना नहीं के बराबर रह जाती है।

शिक्षा ही की तरह अग्निपथ योजना को लेकर राज्यपाल को सौंपे गये ज्ञापन में भी पार्टी की गंभीरता नजर नहीं आती है। क्योंकि आज केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी लाने की योजना बना दी है। इस भागीदारी में 100 स्कूल खोले जाने की योजना है। इसके पहले चरण में 21 स्कूल खोले जा रहे हैं। यह स्कूल वर्तमान में चल रहे सैनिक स्कूलों से भिन्न होंगे। क्योंकि वर्तमान में चल रहे 35 सैनिक स्कूलों में से 33 रक्षा मंत्रालय की सोसायटी द्वारा दो सरकार चला रही है। एक उत्तर प्रदेश सरकार तथा दूसरा जम्मू कश्मीर द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन नये स्कूल एन.जी.ओ/प्राइवेट स्कूल/राज्य सरकारों की भागीदारी से चलाये जायेंगे। इस योजना से सैनिक स्कूलों के संचालन में प्राइवेट सैक्टर का दखल आ जायेगा। सरकार और उसके समर्थक इस नीति का समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक दल इस पहलू पर खामोश हैं। जबकि सेना जैसे संस्थान में ऐसे नीतिगत फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसे में आज जब अग्निपथ पर युवा आक्रोशित है और यह प्राइवेट सैक्टर की प्रस्तावित भागीदारी भी आने वाले समय में इस युवा को सीधे प्रभावित करेगी। इस परिपेक्ष में आज राजनीतिक दलों और दूसरे विचारकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। इस पर किसी भी दल की कैजुअल अप्रोच उसके लिए घातक सिद्ध होगी। आप की प्रदेश इकाई द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में इस पर खामोशी पार्टी की गंभीरता को लेकर कई सवाल खड़े कर देती है।

Ministry of Defence approves 21 new Sainik Schools in partnership mode from academic year 2022-2023

Ministry of Defence (MoD) has approved setting up of 21 new Sainik Schools, in partnership with NGOs/private schools/State Governments. These schools will be set up in the initial round of the Government's initiative of setting up of 100 new Sainik schools across the country in partnership mode. They will be distinct from the existing Sainik Schools

Aam Aadmi Party (Himachal Pradesh)

Dyerton bizhub, Verma apartment, Tallend Bypass Road, Khalini, shimla-171002
Phone : +91 70451 70451 Email : himachalpardeshaap@gmail.com

Election Symbol: Broom

To,
Sh. Rajendra Arlekar
Hon'ble Governor
Government of Himachal Pradesh

Date: 19 June 2022

Subject: The immediate roll-back and re-deliberation of the Agnipath scheme announced by the Union Government.

Dear Sir,

It is with a sense of responsibility as the president of Aam Aadmi Party, Himachal Pradesh that I write to you to draw your attention to this issue of grave concern. On 14 June 2022, the Union Cabinet approved the Agnipath scheme which involves only a four-year long period of service for young individuals willing to join the Armed Forces.

The Indian Armed Forces have been a beacon of hope representing the highest standards of professionalism, service, long standing tradition, and ethos. However, this recent modification to the basic structure of the army has justifiably caused great anguish among youngsters aspiring to serve the country. This controversial 'contractualization' of the Armed Forces has only shattered the dreams of these young aspirants.

Within the past two days we have witnessed nation-wide protests by the youth and insufficient attempts at the last minute by the Union Government to save face. I would like to highlight the following issues for your kind attention:

A. Jawans need peace of mind and job security.

A jawan not only serves the nation but also has the responsibility to support his family, which the union government is failing to understand. A jawan posted on the border need full concentration and a peace of mind to serve and protect the country. However, if that jawan is busy contemplating career moves or wondering how his family will survive after his retirement at the age of 21, he will find it harder to serve our country.

A jawan just out of school, who has not completed any higher education will find it harder to find a new job after this 'retirement from the army'. The careers of youngsters joining the army though this scheme shall be hanging in balance with no sufficient planning done by the Union Government on how they plan to tackle this.

B. Scheme has overlooked issues of inadequate training.

Agnipath scheme entails for Agniveers to undergo a 6-month crash course in training. An abnormally short period of training will have adverse consequences on the quality of service discharged. Resultantly, we will be saddled without sufficient leadership and experience amongst the troops facing the nation's greatest security challenges.

C. Experiments should not be imposed en-masse.

Any new scheme should first be run through a pilot and preferably outside of the Indian Army and the conclusions drawn from there could have provided an opportunity to deliberate before making this decision. A consultative exercise could have followed thereafter to avoid national embarrassment and despair amongst the youth.

For the reasons highlighted above, the Union Government should immediately roll-back the Agnipath scheme and resume the regular recruitment process for the current year. We are experiencing a great deficit in new recruits, and shortcuts that put our jawans at risk cannot be the solution. We cannot make the opportunity to serve the country in the Armed Forces a secondary option for anyone.

On behalf of the youth of Himachal Pradesh, I implore you to request the Union Government to roll-back the Agnipath scheme. The roll-back should give the Union Government sufficient time to re-deliberate on the scheme and provide them an opportunity to consult the aspirants who are affected the most by this sudden decision affecting their fate. The National Convenor of the Aam Aadmi Party and the Hon'ble Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal, has also urged the Union Government to immediately roll-back the scheme and to allow the youth to serve this country in a permanent and non-temporary manner.

Your Sincerely,

Surjeet Thakur
President
Aam Aadmi Party
Himachal Pradesh

अब अदाणी के 280 करोड़ बने जयराम सरकार के गले की फांस

शिमला/शैल। जयराम सरकार 70,000 करोड़ के कर्ज के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। सरकार को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से भी कोई बड़ी आर्थिक सहायता नहीं मिल पायी है। यह कैग रिपोर्ट ने सामने ला दिया है। ऐसे में जब चुनावी वर्ष में मोदी के विश्वासपात्र अदाणी के 280 करोड़ 9% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ से आ जाये तो यह सरकार के लिये कैसी स्थिति पैदा कर देगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्मरणीय है की उच्च न्यायालय की जस्टिस संदीप शर्मा पर आधारित एकल पीठ ने 12 अप्रैल को यह फैसला सुनाया है की 960 मेगावाट की जंगी-थोपन-पवारी परियोजना में ब्रैकल एन.वी.के नाम पर अदाणी पावर से आये 280 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम को 9% ब्याज सहित अदाणी पावर को वापस लौटाया जाये। स्मरणीय है कि 2006 में वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में 960 मैगावाट की यह परियोजना नीदरलैंड की कंपनी ब्रेकल एन.वी को दी गयी थी। लेकिन किन्ही कारणों से यह कंपनी 280 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम अदा नहीं कर पायी। ऐसा न कर पाने पर रिलायंस ने इस आवंटन को चुनौती दे दी। सरकार बदल चुकी थी। धूमल सत्ता में थे मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था अदाणी ने ब्रेकल के नाम पर 280 करोड़ ब्याज सहित जमा करवा दिये। मामला उठा कि जब अदाणी ब्रेकल एन.वी. का पार्टनर ही नहीं है तो उसने किस हैसियत से यह रकम जमा करवायी और सरकार ने इसे स्वीकार कैसे कर लिया। मामला उच्च न्यायालय से होकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। रिलायंस भी पीछे हट गया। परियोजना ब्रेकल एन.वी. रिलायंस और अदाणी किसी को भी नहीं मिल पायी। अब जयराम सरकार ने इसे एसजेवीएनएल को सौंपा है। लेकिन इस सबके बीच अदाणी के 280 करोड़ का मामला खड़ा रहा। 2015 में वीरभद्र सरकार ने इस परियोजना को रिलायंस को देने का फैसला लेते हुये यह भी फैसला दिया था कि इसमें रिलायंस से जो पैसा मिलेगा उससे अदाणी का पैसा लौटा दिया जायेगा। लेकिन यह परियोजना फिर रिलायंस को नहीं मिल पायी और वीरभद्र सरकार ने पैसा लौटाने का फैसला वापस ले लिया। बल्कि उस समय योग गुरु स्वामी रामदेव भी चर्चा में आ गये थे। फिर सरकार बदल गयी और 2019 में अदाणी फिर से उच्च न्यायालय पहुंच गये। लेकिन जयराम सरकार ने फैसला ले लिया कि यह रकम विभिन्न उपलब्धियों के कारण जब्त कर ली गयी है। इसलिये इसे वापस नहीं किया जायेगा। लेकिन अब अदालत ने वीरभद्र सरकार के दौरान लिये इस फैसले के आधार पर की रिलायंस से पैसा मिलने पर अदाणी को लौटा दिया जायेगा पर यह निर्देश सुना दिये की दो माह के भीतर ब्याज सहित यह रकम अदाणी को लौटा दी जाये। अदालत ने साफ कहा है कि सरकार अपने फैसले को ऐसे नहीं बदल सकती। फैसले को एक माह से ज्यादा का समय हो गया। अपील का सामान्य समय निकल गया है। अदाणी ने उच्च न्यायालय में केविएट भी दायर कर रखी है। ऐसे में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस मामले पर सबकी निगाहें लगी हुई है। वैसे कांग्रेस और वाम दल अपने-अपने कारणों से इस पर चुप हैं। आम आदमी पार्टी को इसकी जानकारी ही नहीं है।